PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 042
दि. 11.06.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था', एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर देश के पहले पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी के इस खास रिकॉर्ड पर एनडीए उनका खास सम्मान और अभिनंदन करने जा रहा है।

आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है: पीएम मोदी

दिल्ली: ठऊअ नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'कल के विकसित भारत की गारंटी है,आज का आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है। आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की आकांक्षाओं का वाहक हमारा मध्यम वर्ग है, नींव मध्य वर्ग है। इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने में लगी है... 2014 से पहले मध्यम वर्ग कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था। जटिल टैक्स सिस्टम, आमदनी के सीमित स्रोत और टैक्स का बड़ा बोझ, ये सब सामान्य व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन की चुनौती होती थी... हमने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को समझा इसलिए आज 12 लाख रुपये तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आज देश में सरल और फेस लेस टैक्स सिस्टम है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका जीवन आसान हुआ है...'

हम आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था:पीएम मोदी

दिल्ली: ठऊअ नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आज दुनिया के बड़े-बड़े देशों की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वाटर तो, जो 31 मार्च को खत्म हुआ है, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही है। ये सफलता इतनी आसान नहीं है... हम आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।'

12 वर्षों में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ: पीएम मोदी

ठऊअ नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'ठऊअ के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये

भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे-धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है और बड़ी ही चतुराई से धीमी विकास को एक नाम दिया था, 'हिंदू ग्रोथ रेट' यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में न सुशासन था, न नीति, न नीयत और ना निर्णय। पहली बार अटल जी के नेतृत्व में ठऊअ सरकार आई तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ों रुपये के घोटालों में घसीट दिया। देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में ठऊअ की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नीयत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है।'

देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपने भरोसा हमें सौंपा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'साल 2014 में जब ठऊअ की जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपने भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि ठऊअ परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है।'

मैं आज देश की महान जनता को नमन करता हूं: पीएम मोदी

दिल्ली: ठऊअ नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, '2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को नमन करता हूं, जनता-जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।' पीएम के कार्यक्रम इस प्रकार सम्पन्न हुए, दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश भर के ठऊअ नेताओं के साथ बैठक की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राजिंदर नगर दुर्गा मंदिर में पूजा में हिस्सा लिया।

पीएम मोदी ने नेताओं के साथ खाई झालमुड़ी

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की बैठक के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध झालमुड़ी का स्वाद लिया और अपने हाथों से उन्हें परोसा भी। इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी नेताओं के साथ हल्के-फुल्के अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में 12 साल का ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा कर एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।

भारत को सही वक्त पर सही नेता मिला..., आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे दी पीएम मोदी को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में 12 साल पूरे कर लिए हैं. उन्होंने यह अनोखा रिकॉर्ड 10 जून को बनाया है. पीएम मोदी ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी. अब एनडीए के गठबंधन के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए, उन्हें इस उपलब्धि की बधाई दी है.

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मोदी जी का सिंगल ऐजेंडा नेशन फास्ट है. मोदी जी एक महान देश के नेता है. भारत को सही वक्त पर सही नेता मिला. मोदी दुनिया के महान नेताओ में से एक है.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज भारत मोदी के नेतत्व मे नये छितिज को छू रहा है.

मोदी जी के मजबूत नेतत्व की बदौलन देश एक मजबूत बन रहा है. मोदी जी एक तपस्वी है और वो त्रिकालदर्शी है. हम एनडीए के सभी घटक उनके साथ खुश है. मोदी के 12 साल पर कोई कंलक नही लगा. मोदी जी हर पल राष्ट्र के लिये समर्पित है मोदी जी का हमारे गठबंधन के नेताओं से साथ आत्मीय संबध है. मोदी ने सबका साथ सबका विश्वास के साथ काम किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर 12 साल पूरे किए. चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिनों के कार्यकाल के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

अगर 1947 से 1952 तक के उस दौर को भी जोड़ा जाए, जब जवाहरलाल नेहरू बिना आम चुनाव के प्रधानमंत्री थे, तो उनका कुल कार्यकाल 6,131 दिनों का बनता है. इसलिए कुल कार्यकाल के मामले में नेहरू अब भी आगे हैं।

कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2ए (कोटेश्वर मार्ग से एयरपोर्ट गलियारे) को स्वीकृति दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2(ए) को स्वीकृति दे दी है। इस गलियारे की लंबाई 6.032 किलोमीटर है और इसमें 5 स्टेशन (4 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड) शामिल हैं। चरण 2(ए) के कार्यान्वित होने पर अहमदाबाद-गांधीनगर गलियारे में 77.63 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा। चरण 2(ए) कॉरिडोर में स्थित स्टेशनों के नाम हैं- आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती नदी, सरदार नगर और एयरपोर्ट।

इस परियोजना की कुल लागत, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) भी शामिल है, 2,169.04 करोड़ रुपये होगी।

लाभ और विकास को बढ़ावा देना:

अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का चरण 2(ए) शहर के बुनियादी

ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। चरण 2(ए) शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क का एक बड़ा विस्तार है।

बेहतर सम्पर्क: अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के चरण 2(ए) में लगभग 6.032 किलोमीटर के नए मेट्रो कॉरिडोर के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डे से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करके और उन प्रमुख आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़कर सार्वजनिक परिवहन को काफी हद तक बढ़ाना है, जिनमें वर्तमान में कुशल ट्रांजिट पहुंच का अभाव है।

इस चरण का उद्देश्य आवासीय और वाणिज्यिक केंद्रों सहित प्रमुख क्षेत्रों को अहमदाबाद-गांधीनगर गलियारे के साथ सुचारू रूप से एकीकृत करना है। इसके अलावा, 2029 के विश्व पुलिस खेलों और 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आसपास के क्षेत्र में खेल सुविधाओं को बढ़ाने की भी संभावना है।

उपराष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित फिल्म निमार्ता भरतिराजा के निधन पर शोक व्यक्त किया

उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने प्रतिष्ठित फिल्म निमार्ता भरतिराजा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

अपने संदेश में श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि भरतिराजा एक

दूरदर्शी कहानीकार थे, जिन्होंने ग्रामीण भारत की आत्मा और मानवीय भावनाओं की गहराई को उल्लेखनीय प्रामाणिकता के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लाकर तमिल सिनेमा में क्रांति ला दी।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपनी विशिष्ट सिनेमाई भाषा, अविस्मरणीय पात्रों और कालजयी फिल्मों के माध्यम

खान सर विवाद में नया मोड़, रौशन आनंद की जमानत अर्जी पर होगा तगड़ा ड्रामा, कब आएगा बड़ा फैसला? बीते दिनों कई बार विरोध प्रदर्शन

(जीएनएस)।

पटना में खान सर की कोचिंग से जुड़े फायरिंग और बवाल मामले में गिरफ्तार किए गए शिक्षक रौशन आनंद की कानूनी लड़ाई अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब उनकी जमानत याचिका जिला जज की अदालत में दाखिल की गई है। इस मामले को लेकर छात्रों में लगातार नाराजगी देखी जा रही है और बीते दिनों कई बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं।

दूसरी ओर खान सर के दोनों बॉडीगाड्र्स की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जबकि खुद खान सर को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिल चुकी है। ऐसे में इस पूरे मामले पर सभी की नजरें अदालत के अगले फैसलों पर टिकी हुई हैं।

रौशन आनंद की जमानत याचिका सोमवार को मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उनके वकीलों ने जिला जज की अदालत का रुख किया है। अब नई जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और अदालत यह तय करेगी कि उन्हें राहत मिल सकती है या नहीं। पुलिस ने रौशन आनंद को 3 जून को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई 2 जून को खान सर की कोचिंग के बाहर हुए हमले और गोलीबारी की घटना के बाद की गई थी।

रौशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब तक पटना में तीन बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं। मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि बिना किसी निष्पक्ष जांच समिति के किसी व्यक्ति को जेल भेजना सही नहीं है। उनका कहना था कि पहले पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए।

छात्रों ने यह भी कहा कि रौशन आनंद से जुड़े हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान यह सवाल भी उठाया गया कि एक आरोपी को जमानत मिल जाती है जबकि दूसरे को जेल में रखा जाता है। छात्रों का दावा था कि जो व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था, वह जेल में है जबकि अन्य लोग बाहर हैं।

इसी मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर बुधवार को फिर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से केस डायरी और दोनों आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी मांगी थी। अदालत ने दोनों गाड्र्स की बेल पेटीशन खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान जिला अभियोजक की ओर से प्रदीप कुमार के हथियार के उपयोग पर सवाल उठाए गए थे। अभियोजन पक्ष का कहना था कि उन्हें हथियार व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया था। अभियोजन ने अदालत में तर्क दिया कि सुरक्षा के लिए मिले हथियार का इस्तेमाल किसी भी तरह से लोगों के बीच डर का माहौल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि आज की सुनवाई में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा सकता है।

इस बीच फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दी है। अदालत ने फिलहाल उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अगली सुनवाई या नए आदेश तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। हालांकि अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। खान सर की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी और किसी तरह का डर या दहशत फैलाना उद्देश्य नहीं था। अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के बाद अंतरिम राहत दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख तय की है।

कांग्रेसी ने कहा '100 टका टंच माल', राहुल गांधी ने दिया इनाम, अब नामांकन रद्द

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों शह-मात का खेल तेज है। राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने अपनी एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाने के बाद तूफान खड़ा कर दिया है। 10 जून 2026 को कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा।

अभिषेक मनु सिंघवी समेत नेताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को गलत और कानून के खिलाफ बताया। लेकिन इस घटना के पीछे की कहानी सिर्फ नामांकन रद्द होने की नहीं, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति, ईमानदारी की मिसाल और पुराने विवादों की है। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं

मध्य प्रदेश विधानसभा सचिव और रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने 9 जून को मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट और राज्य बीजेपी महासचिव

राहुल कोठारी की आपत्ति पर कार्रवाई हुई। आधार बताया कि नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे में एक पुराने मामले का खुलासा नहीं किया गया।

कांग्रेस का दावा है कि यह मामला 2022 का है, हैदराबाद में एक निजी शिकायत (हरासमेंट संबंधी), जिसमें सिर्फ नोटिस आया था। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, न कोई चार्जशीट। कोर्ट ने सिर्फ यह पूछा था कि आगे सुनवाई शुरू हो या नहीं। पार्टी का कहना है कि ऐसे नोटिस को 'आपराधिक मामले' की श्रेणी में गिनना कानून के मुताबिक गलत है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'इस आधार पर नामांकन रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है।'

कांग्रेस ने इसे बीजेपी की 'सीट चोरी' की साजिश बताया। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस अब दूसरे उम्मीदवार नहीं उतार सकती क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख बीत चुकी है। इससे बीजेपी के तीन उम्मीदवार, तरुण चुघ, राजनेश अग्रवाल और महेश केवट बिना मुकाबले जीत सकते हैं।

मीनाक्षी नटराजन (जन्म 23 जुलाई 1973) मध्य प्रदेश की नागदा की रहने वाली हैं।

पश्चिम बंगाल : कांग्रेस में विलय करने जा रही है ममता बनर्जी? मर्जर की खबरों पर क्या बोली तृणमूल कांग्रेस पार्टी

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उथल-पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) और कांग्रेस के संभावित विलय की चचाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि, दोनों दलों ने बुधवार, 10 जून को इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि कांग्रेस और TMC के विलय का कोई प्रस्ताव न तो विचाराधीन है और न ही इस दिशा में कोई औपचारिक बातचीत चल रही है।

इसके बावजूद राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि दोनों दल भविष्य में संभावित चुनावी सहयोग और साझा राजनीतिक मुद्दों पर साथ काम करने के विकल्प खुले रखे हुए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और TMC के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार संवाद बना हुआ है।

कांग्रेस और TMC के विलय की अटकलों को उस समय और बल मिला जब हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक

विश्लेषकों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि विपक्षी राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बैठक का उद्देश्य विपक्षी एकजुटता और INDIA गठबंधन को मजबूत करना था, न कि किसी प्रकार का संगठनात्मक विलय।

ANI के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय और INDIA गठबंधन को मजबूत बनाने पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने अगस्त में हैदराबाद में होने वाली अगली INDIA गठबंधन बैठक को लेकर भी सहमति जताई है। इससे संकेत मिलते हैं कि भले ही विलय की संभावना नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए दोनों दल साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक- इन अटकलों के पीछे एक बड़ी वजह TMC के भीतर चल रहा गंभीर राजनीतिक संकट भी माना जा रहा है। पार्टी इस समय अपने गठन के बाद के सबसे बड़े आंतरिक विद्रोह का सामना कर रही है।

बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी का दावा है कि TMC के 58 विधायक खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बाद में उन्होंने यह संख्या बढ़कर 64 विधायकों तक पहुंचने का दावा भी किया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि पार्टी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती दी है और इसी कारण विभिन्न राजनीतिक संभावनाओं पर चचाएं तेज हुई हैं।

सम्पादकीय

हो रहा पीओके की निर्दोष जनता पर अत्याचार

पाक अधिवृत कश्मीर (पीओके) की पुलिस और सैन्य बलों द्वारा 20 से अधिक प्रदर्शनकारी नागरिकों की हत्या के लिए सीधे इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया और विश्व समुदाय से आग्रह किया कि निर्दोष जनता पर अत्याचार का पाकिस्तान को दोषी ठहराएं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने भी गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान के सुरक्षाबलों की बर्बरता की निन्दा की।

दरअसल सोमवार को पीओके के रावलाकोट में सेना ने प्रदर्शनकारी नागरिकों पर फायरिंग करके 120 लोगों को मार डाला था जबकि पुलिस ने पूरे गुलाम कश्मीर में कई स्थानों पर हुए प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाने के लिए बल प्रयोग किया जिसमें काफी लोग मारे गए और ज्यादातर घायल बताए जा रहे हैं। असल में पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में विदेशी मीडिया पर रोक लगा रखी है। विदेशी मिशन के राजनायिकों को भी इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं मिलती। रही बात मानवाधिकार संगठनों की तो पाकिस्तान जैसे देश में मानवाधिकारवादियों के लिए मानवाधिकार तो आतंकियों और जल्लाद सैन्य कर्मियों के ही होते हैं। इसीलिए भारत ने विश्व समुदाय से अनुरोध किया है कि पाकिस्तान द्वारा गुलाम कश्मीर के लोगों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन उस क्षेत्र में जाकर वास्तविकता को देखें।

सच तो यह है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ यही आवाज विश्व मंचों पर बहुत पहले ही उठाना चाहिए थी। आखिर पीओके भी तो जम्मू-कश्मीर का ही हिस्सा है और जम्मू-कश्मीर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत वैधानिक विलय के बाद भारत का अभिन्न अंग है। यह तो भारत का अधिकार है कि वह बलपूर्वक कब्जाए गए जिस भूभाग के निवासियों पर इस्लामाबाद की सरकार के इशारे पर लाठी, गोली और बम से हमला वदी वाले भेंड़ियों ने किया, उनकी निन्दा करे क्योंकि जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है वे हमारे अपने हैं।

मजे की बात तो यह है कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पहले भी कह चुके हैं कि हमारे लोगों पर पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। मतलब यही है गुलाम कश्मीर के लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितने कि जम्मू-कश्मीर के भारतीय।

बहरहाल भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को गुलाम कश्मीर में सरकारी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, इसकी आशंका सोमवार को पाकिस्तान की मीडिया में व्यक्त की गई थी। मीडिया चैनलों पर बैठकर पूर्व सैन्य अधिकारियों, राजनायिकों व पत्रकारों ने दो टूक शब्दों में स्वीकार किया कि पाक सेना की हैवानियत की वजह से अब भारत को बहुत अच्छा अवसर मिल गया है और वे पाक सेना की बर्बरता का मुद्दा जोर-शोर से उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी शिकायत करें।

पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने पाक सेना और सरकार को जमकर लताड़ा। लब्बोलुआब यह है कि भारत को गुलाम कश्मीर की पीड़ित जनता के साथ खड़ा होने का समय आ गया है। बेहतर तो यह होता कि यदि पाकिस्तान पीओके को नहीं संभाल पा रहा है तो उसे इस क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। किन्तु पाकिस्तान से ऐसी शराफत की उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद तो यही है कि गुलाम कश्मीरी शीघ्र ही आजादी पाने के लिए क्रूर पाक सैनिकों को अपनी जमीन से भागने पर मजबूर कर देंगे।

उ.प्र. चुनाव से पहले योगी का आ गया 'त्रिशूल' फॉमूर्ला... धड़ाधड़ एनकाउंटर, गरजे बुलडोजर और सनातन के रथ पर होंगे सवार!

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. सूबे में एक तरफ जहां माफियाओं पर धड़ाधड़ एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन से कानून व्यवस्था का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 'कट्टर हिंदुत्व' के एजेंडे को धार देकर विपक्ष के पीडीए फॉमूर्ले को ध्वस्त करने की बड़ी तैयारी है.

(जीएनएस)।

लखनऊ. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने में बेशक 7-8 महीने का वक्त है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही राज्य की राजनीतिक बिसात पर अपने सबसे घातक मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं. विपक्ष के जातिगत समीकरणों ढऊ्र यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सोशल इंजीनियरिंग की काट ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद ह्यकालभैरव अवतारह्न में लौट आए हैं. इस बार उनकी रणनीति दोगुनी आक्रामक है, जहां एक तरफ अपराधियों की रीढ़ तोड़ने के लिए बुलडोजर और एनकाउंटर की रफ्तार बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज को एकजुट करने के लिए ह्यकट्टर हिंदुत्वह्न के मुद्दे को चुनावी पिच पर सबसे आगे रख दिया गया है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने इस बार ह्यत्रिशूल रणनीतिह्न तैयार की है, जो कानून-व्यवस्था, राष्ट्रवाद-हिंदुत्व और धड़ाधड़ लिए जा रहे प्रशासनिक फैसलों पर टिकी है.

पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सूबे के बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एनकाउंटर ड्राइव को तेज कर दिया है. गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर से लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पैर में गोली लगने की घटनाएं अचानक अब रूटीन बन चुकी हैं. सिर्फ अपराधी ही नहीं, बल्कि उनके अवैध निमार्णों और जमीनों पर मुख्यमंत्री का पसंदीदा ह्यब्रांड बुलडोजरह्न दोबारा पूरी ताकत से गरजने लगा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है.

योगी के एक्शन पर सपा का दो टूक जवाब, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्ष ने इन एनकाउंटरों को ह्यप्रायोजितह्न बताकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सीएम योगी ने दो टूक लहजे में साफ कर दिया कि 'जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून अपने सबसे सख्त दायरे में रहकर काम करेगा, समाज के दुश्मनों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होगी.'

विकास और सुशासन के दावों के साथ-साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में ह्यसनातन और हिंदुत्वह्न के एजेंडे को बेहद धारदार बना दिया है. मऊ और लखनऊ की हालिया जनसभाओं में उनके बयानों ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव को ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक गौरव के मुद्दे पर ले जाने की पूरी तैयारी में हैं.

योगी सभाओं में क्या कह रहे हैं?

सीएम योगी अपने भाषणों में जनता को सीधे संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि 'आपका एक वोट केवल सरकार नहीं चुनता, बल्कि आपके एक वोट की ताकत ने 500 साल की गुलामी के कलंक को धोकर अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया है. यही एक वोट यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाता है.' इसके जरिए वे बंटे हुए हिंदू वोट बैंक को जातिगत दीवारों से ऊपर उठाकर एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं.

योगी का तीसरा और अंतिम प्रहार

योगी धड़ाधड़ प्रशासनिक फैसले और युवाओं को साधने की कोशिश में लग गए हैं. चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने युवाओं और सरकारी व्यवस्था को लेकर कई कड़े और त्वरित फैसले लिए हैं. जैसे पेपर लीक पर सख्त कानून. परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त से सख्त जेल और जुमार्ने का प्रावधान. नौसेना शौर्य वाटिका जैसे सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद से जुड़े प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के साथ युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है.

जानकारों की राय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भली-भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए उन्हें अपने मूल ह्यफायरब्रांडह्न और ह्यकड़क प्रशासकह्न वाले नैरेटिव पर ही दांव लगाना होगा. अपराधियों पर प्रशासनिक चाबुक और मंचों से हिंदुत्व की हुंकार, यही वह चक्रव्यूह है जिसमें वे विपक्ष के जातिगत समीकरणों को उलझाना चाहते हैं.

ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासी जंग बेहद तीखी होने वाली है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग होगी, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का ह्यकालभैरव अवतारह्न और उनका आजमाया हुआ बुलडोजर मॉडल होगा.

भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक 10 दिवसीय प्रदर्शनी मंगोलिया में संपन्न

मंगोलिया में लगभग एक लाख श्रद्धालुओं ने अर्हंत सारिपुत्र और अर्हंत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए

(जीएनएस)।

भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों, अर्हंत सारिपुत्र और अर्हंत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेष आज मंगोलिया के उलानबातर स्थित गंडन तेगचेनलिंग मठ में आयोजित दस दिवसीय सफल प्रदर्शनी के बाद भारत वापस लाए गए हैं। गंडन तेगचेनलिंग मठ के अनुरोध पर, संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय ने मध्य प्रदेश सरकार, श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी और इंटरनेशनल बुद्धिष्ट कॉन्फेडरेशन (आईबीसी) के सहयोग से 31 मई से 9 जून, 2026 तक पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी 31 मई, 2026 को मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आम जनता के लिए खोली गई।

पवित्र अवशेषों को 30 मई, 2026 को असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा मंगोलिया के शिक्षा मंत्री श्री एनख-अमगलान और गंडांटेगचेनलिंग मठ के परम पूज्य खंबा नोमुन खान गेशे लहारम्पा डी जावजांडोरज को समारोहपूर्वक सौंपा गया।

इस प्रदर्शनी की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री खुरेलसुख उखना की भारत यात्रा के दौरान की थी। भारत और मंगोलिया बौद्ध धर्म पर आधारित गहरे सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध साझा करते हैं और इस प्रदर्शनी ने मंगोलिया के लोगों को पवित्र अवशेषों के दर्शन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। 10 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी के दौरान, मंगोलिया भर से लगभग एक लाख श्रद्धालुओं ने मठ में दर्शन किए। मंगोलिया की जनसंख्या लगभग 34 लाख है।

अब तक ये अवशेष केवल थाईलैंड और मंगोलिया भेजे गए हैं। गौरतलब है कि जून 2022 में मंगोलिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी एक बेहद सफल और यादगार आयोजन था।

प्रदर्शनी के दौरान, भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और इंटरनेशनल बुद्धिष्ट कॉन्फेडरेशन ने बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जिनकी जनता, भिक्षुओं और विद्वानों द्वारा बहुत सराहना की गईः

i) सारिपुत्त और मोग्गलाना झ ज्ञान, भक्ति और अवशेषों की यात्रा झ इंटरनेशनल बुद्धिष्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा

ii) भारत से मंगोलिया तकः आंतरिक एशिया में बुद्ध धम्म का प्रसार - इंटरनेशनल बुद्धिष्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा

iii) प्रकाश के पात्रः प्रतिमा विज्ञान, अवशेष और धम्म का मार्ग (भारत के संग्रहालय संग्रहों के माध्यम से शाक्यमुनि बुद्ध की यात्रा) - भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा

पवित्र अवशेषों को प्रोटोकॉल और सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है। इन्हें 30 मई, 2026 को भारतीय वायु सेना के एक विशेष विमान द्वारा मंगोलिया लाया गया था, जिसमें असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। आज भारतीय वायु सेना के एक विशेष विमान द्वारा लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इन अवशेषों को भारत वापस लाया गया। गंडन तेगचेनलिंग मठ में औपचारिक स्वागत और विदाई समारोह आयोजित किए गए।

मंगोलिया सरकार ने प्रदर्शनी के लिए पूर्ण समर्थन दिया, जबकि गंडन तेगचेनलिंग मठ ने पवित्र अवशेषों की आदरणीय स्थिति के अनुरूप आयोजन के धार्मिक पहलुओं की देखरेख की। आज मठ में आयोजित समापन समारोह के दौरान, परम पूज्य खंबा नोमुन खान गेशे लहारम्पा डी. जावजांदोरज, महामहिम श्री एनख-अमगलान, लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना, श्रीलंका के महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष पूज्य बनगला उपतिस्सा थेरो और इंटरनेशनल बुद्धिष्ट कॉन्फेडरेशन के महासचिव शारत्से खेनसुर रिनपोचे जांगचुप चोडेन सहित वक्ताओं ने मंगोलिया में प्रदर्शनी को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

पवित्र अवशेषों को भारत वापसी से पहले, परम पूज्य श्री एनख-अमगलान और परम पूज्य वेन. खंबा नोमुन खान गेशे लहारम्पा डी. जावजांदोरज द्वारा लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना को विधिवत सौंप दिया गया। प्रस्थान से पहले हवाई अड्डे पर, मंगोलिया में भारत के राजदूत श्री अतुल मलहारी गोत्सुर्वे ने लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल को एक मंगोलियाई पौधा भेंट किया। यह पौधा लद्दाख में भारत और मंगोलिया के बीच अटूट मित्रता और आध्यात्मिक बंधन के प्रतीक के रूप में लगाया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल और गंडन तेगचेनलिंग मठ ने प्रदर्शनी के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग के लिए मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन ने भारत और मंगोलिया के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया है।

क्या है बेन स्टोक्स का नाइट क्लब विवाद? करियर खत्म होने का खतरा, मुश्किल में इंग्लैंड के कप्तान

(जीएनएस)।

इंग्लैंड क्रिकेट इस समय एक बड़े विवाद के केंद्र में है। टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का नाम एक नाइट क्लब घटना से जुड़ने के बाद सुर्खियों में है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब इंग्लैंड एंड वेल्स को जांच शुरू करनी पड़ी है और क्रिकेट जगत में स्टोक्स की कप्तानी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन इस विवाद ने इंग्लैंड क्रिकेट में हलचल जरूर मचा दी है। इंग्लैंड ने हाल ही में न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में हराया था। जीत के बाद कप्तान बेन स्टोक्स, तेज गेंदबाज गस एटकिंस और कुछ रग्बी खिलाड़ी लंदन के चेल्सी इलाके में स्थित एक नाइट क्लब पहुंचे। रिपोर्ट्स के अनुसार एउइ द्वारा लागू किए गए आधी रात की पाबंदी के बावजूद खिलाड़ी देर रात तक क्लब में मौजूद रहे।

मारपीट की नौबत आई

इसके बाद क्लब के श्क्ढ एरिया में विवाद हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रग्बी खिलाड़ी ने कथित

तौर पर एटकिंसन को निशाना बनाकर मुक्का चलाया, लेकिन वह एउइ के एक सुरक्षा अधिकारी को जा लगा। हालांकि अब तक किसी रिपोर्ट में स्टोक्स या एटकिंसन को झगड़े की शुरूआत करने वाला नहीं बताया गया है।

ECB अभी क्या कर रहा है?

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर "टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन" की जांच शुरू कर दी है। बोर्ड ने कहा है कि वह घटना की पूरी जानकारी जुटा रहा है और क्रिकेट रेगुलेटर को भी सूचित कर दिया गया है। दूसरे टेस्ट के लिए टीम चयन और खिलाड़ियों की उपलब्धता पर फैसला जांच के बाद लिया जाएगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि स्टोक्स और एटकिंसन दूसरे टेस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, हालांकि एउइ ने अभी तक कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया है।

क्या कप्तानी पर खतरा है?

फिलहाल इसका जवाब हां है, खतरा है लेकिन फैसला नहीं हुआ है। ब्रिटिश मीडिया की कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्टोक्स अपनी कप्तानी के भविष्य पर विचार कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि वह कप्तानी छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं।

इसके पीछे सिर्फ यह घटना नहीं है। पिछले एक साल में इंग्लैंड टीम की "ड्रिंकिंग कल्चर" को लेकर कई विवाद सामने आए थे, जिसके बाद एउइ ने कर्फ्यू जैसे नियम लागू किए थे। ऐसे में अगर कप्तान ही नियम तोड़ते पाए जाते हैं तो मामला और गंभीर माना जा रहा है।

क्या करियर पर भी खतरा है?

अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि स्टोक्स का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म होने वाला है। न तो पुलिस केस दर्ज हुआ है और न ही उन पर किसी शारीरिक हमले का आरोप है। जांच मुख्य रूप से टीम नियमों के उल्लंघन पर केंद्रित है। हालांकि अगर एउइ कड़ा रुख अपनाता है तो उन्हें निलंबन, जुमार्ना या कप्तानी से हटाए जाने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। करियर समाप्त होने की बातें फिलहाल केवल अटकलें हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मानव सुथार अब इंग्लैंड में खेलेंगे, रातोंरात खुली किस्मत और आया बुलावा, डेब्यू टेस्ट में मचाया था तहलका

(जीएनएस)।

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों एक नया नाम हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है और वह नाम राजस्थान के युवा स्पिनर मानव सुथार का है। अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी फिरकी से विरोधियों को घुटने पर लाने वाले मानव सुथार के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगा है।

इस 23 साल के बाएं हाथ के स्पिनर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धमाकेदार शुरूआत करने के ठीक बाद अब इंग्लैंड के मशहूर काउंटी क्लब वॉरिकशायर के साथ एक शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्लब ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि मानव सुथार उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं।

करियर का टर्निंग पॉइंट

यह डील मानव सुथार के करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें काउंटी चैंपियनशिप के अगले दो महत्वपूर्ण राउंड के लिए टीम में शामिल किया गया है। वॉरिकशायर की टीम इस समय अंक तालिका में चौथे स्थान पर है और खिताब की दौड़ में बनी हुई है।

डेब्यू मैच कौन भूल सकता है

मानव सुथार ने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में महज 33 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे और मैच में कुल 7 विकेट लेकर भारत की ऐतिहासिक जीत की कहानी लिखी थी। उनके इसी लाजवाब प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लिश काउंटी क्लब ने उन्हें तुरंत अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी किया धमाल

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आने से पहले भी मानव का फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है जहां उन्होंने 29 मैचों में 129 विकेट अपने नाम किए हैं। वॉरिकशायर के परफॉर्मेंस डायरेक्टर जेम्स थॉमस ने कहा है कि मानव की फिरकी उनके गेंदबाजी आक्रमण को इंग्लैंड की पिचों पर एक नया और मजबूत आयाम देगी। इंग्लिश कंडीशंस तेज गेंदबाजों के लिए आदर्श होती है लेकिन मानव को शायद पिच से फर्क नहीं पड़ना चाहिए।

मैदान पर कब उतर सकते हैं

वह आगामी 12 से 15 जून तक स्कारबोरो में यॉर्कशायर के खिलाफ होने वाले मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद अगले हफ्ते वे टॉन्टन में सोमरसेट के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। अगस्त में होने वाले भारत के श्रीलंका दौरे से पहले मानव के लिए यह अनुभव बेहद काम आने वाला है।

मुनीर की तानाशाही का नया चेहरा, पीओके प्रदर्शन में नेताओं पर लगाया राजद्रोह, 1 करोड़ का रखा इनाम

(जीएनएस)।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी आजाद जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में व्यापक शटर-डाउन हड़ताल देखने को मिली। इस दौरान पाकिस्तान की एजेंसियों और हाल ही में बैन किए गए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों के बीच कई जगह झड़पें भी हुईं। इसी बीच पाकिस्तान की सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए नया तरीका निकाला है।

प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर राजद्रोह का मामला

प्रदर्शन को दबाने के लिए PoK की सरकार ने खअअउ के दो बड़े नेताओं के खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही संगठन के चार नेताओं की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वालों के लिए 1 करोड़ रुपये के इनाम की भी घोषणा की गई है। दूसरी ओर, ढङ्कङ के प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए सभी पक्षों से बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है।

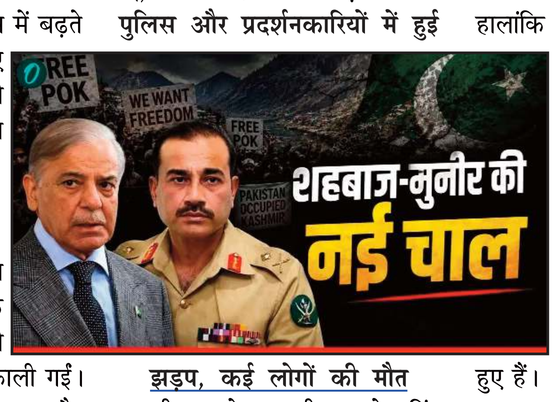

मीरपुर डिवीजन से शुरू हुआ प्रदर्शन

झड़पों की शुरूआत तब हुई जब मीरपुर डिवीजन के कई इलाकों में JAAC की योजना के तहत रैलियां निकाली गईं। इस डिवीजन में मीरपुर, भीमबर और कोटली जिले शामिल हैं। मीरपुर शहर में सैकड़ों प्रदर्शनकारी कायदे-ए-आजम क्रिकेट स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए। इसके बाद उन्होंने प्लाक ब्रिज की ओर मार्च शुरू किया। यहां कोटली जिले की सीमा पर डड्याल से ख्वाजा मेहरान अरशद के नेतृत्व में आई दूसरी रैली भी उनके साथ जुड़ गई, जिससे प्रदर्शन और बड़ा हो गया। **पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प, कई लोगों की मौत**

मीरपुर के बाहरी इलाके पिंड सभरवाल गांव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संक्षिप्त लेकिन तनावपूर्ण झड़प हुई। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार इस दौरान दो पुलिसकर्मी और कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सबसे गंभीर और हिंसक झड़पें कोटली शहर में हुईं। यहां खुइरट्टा तहसील से आए सैकड़ों लोगों का जुलूस शहर में पहुंचा था। हालांकि अधिकारी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों और ढङ्कङ कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने नाम न बताने की शर्त पर दावा किया कि इन झड़पों में एक डॉक्टर और एक महिला समेत कई लोगों की मौत हुई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं।

छत पर खड़े डॉक्टर को लगी गोली

शुरूआती रिपोर्टों के मुताबिक, मृतकों में शामिल डॉक्टर अपने घर की छत पर मौजूद थे। इसी दौरान झड़प के बीच चली एक आवारा गोली उन्हें लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं लगातार बंद रहने के कारण वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करना काफी मुश्किल हो गया है।

दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

इस बीच, JAAC के वरिष्ठ सदस्य और जाने-माने वकील अमजद अली खान की कथित गिरफ्तारी के विरोध में ढङ्कङ बार काउंसिल के आ'ान पर वकीलों ने न्यायिक कार्यवाही का बहिष्कार किया। इससे कानूनी कामकाज भी प्रभावित हुआ। PoK सरकार ने मुजफ्फराबाद निवासी शौकत नवाज मीर और मीरपुर निवासी मेहरान अरशद ख्वाजा के खिलाफ राजद्रोह की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी किए निर्देश में दोनों नेताओं पर भाषणों, लिखित सामग्री, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से राजद्रोह फैलाने का आरोप लगाया गया है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लखनऊ हाईकोर्ट सख्त, गुमशुदा नाबालिग बच्चों के मामलों में पुलिस कमिश्नर से मांगा स्पष्टीकरण; जानें मामला

(जीएनएस)।

लखनऊ, हाईकोर्ट ने राजधानी में गुमशुदा नाबालिग बच्चों के मामलों की जांच में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा गया और नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। अधिकांश बच्चों को बरामद कर लिया गया है, जबकि शेष मामलों में खोज अभियान और जांच तेज करने को कहा गया है।

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी से गुम हुए नाबालिग बच्चों के मामलों में लचर तफ्तीश पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने लखनऊ के सभी थानों से संबंधित ऐसे गुमशुदगी के मामलों में पुलिस कमिश्नर से 10 जून को स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही पुलिस उपायुक्त (डी सी पी) दीक्षा शर्मा को निर्देश दिया थाकि वे ऐसे केसों की निगरानी कर रिपोर्ट पेश करें।

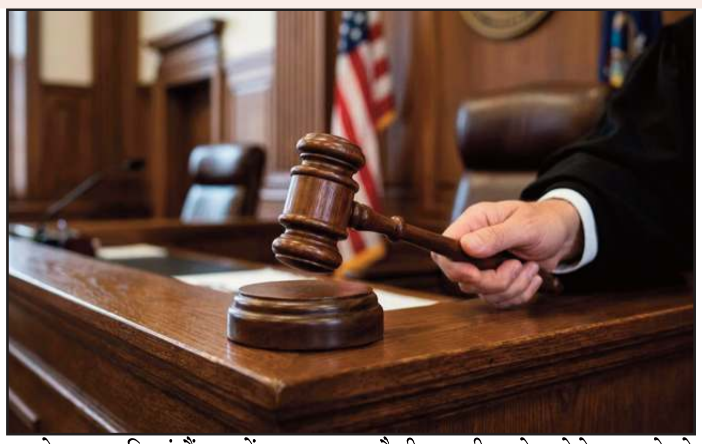

इसके तहत, बुधवार को अदालत को बताया गया कि 1 जनवरी2026 से अब तक कुल 261 लोग लखनऊ से गुम हुए हैं। इनमें अधिकांश नाबालिग लड़के व लड़कियां हैं। इनमें 227 का पता लगाकर बरामद कर लिया गया है। जबकि, 34 अभी भी लापता हैं। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाकर इन लापता लोगों के मामलों की साप्ताहिक निगरानी करने के निर्देश दिए और 3 जुलाई की निगरानी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। जब राजधानी में गुमशुदा लोगों की तलाश मामले में यह हाल है, तो ने जिलों की हालत समझी जा सकती है। कोर्ट के आदेश पर लखनऊ के पूर्वी जो के डी सी पी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी समेत ऐसे मामलो के विवेचक भी पेश हुए। कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाकर कहा कि ऐसे मामलों को विवेचना में सुस्ती, लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।

न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की अवकाश कालीन पीठ ने बुधवार को यह आदेश एक नाबालिग लड़की की और से उसके पिता द्वारा दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में शहर से गुम हुई 12 साल की नाबालिग लड़की की तलाश करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था।

इस नाबालिग लड़की बरामदगी होने पर कोर्ट ने उसके पिता को सौंप दिया। पहले, सुनवाई के समय पेश हुई डी सी पी दीक्षा शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि उनकी अधिकारिता में आने वाले नौ थानों में से 81 लड़कियों (जिनमें अधिकांश नाबालिग हैं), का या तो अपहरण हुआ या फिर वे बहला फुसलाकर भगा ले जाई गईं।

इनमें से 66 को बरामद कर लिया गया है, जबकि, 15 लड़कियां अभी भी गुम हैं। इसपर कोर्ट ने कहा था कि, मौजूदा मामले के अलावा शहर में अन्य और ऐसे मामले हो सकते हैं, जो पुलिस की जानकारी में नहीं होंगें। ऐसे में डी सी पी इन मामलों का पता लगाकर और इनकी निगरानी करके तीन दिन में रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जून को पहले केस के रूप में निर्धारित करके डी सी पी को सभी संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षकों समेत विवेचनाधिकारियों के साथपेश होने का निर्देश दिया था।

पांच लाख रुपए प्रतिमाह वेतन के बाद भी नहीं टिक रहे हैं डॉक्टर, 40 फीसदी पद हैं खाली; बनेगा नया भर्ती बोर्ड

(जीएनएस)।

लखनऊ , यूपी के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के करीब 18,500 पद हैं। इसमें करीब 11 हजार कार्यरत हैं, जबकि 7,500 पद खाली चल रहे हैं।

प्रदेश में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के करीब 18,500 पद हैं। इसमें करीब 11 हजार कार्यरत हैं, जबकि 7,500 पद खाली चल रहे हैं। करीब 2500 विशेषज्ञों के लिए भर्ती प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी भेजा गया है। ग्रामीण इलाके में विशेषज्ञों की कमी का ग्राफ करीब 70 फीसदी तक है।

अपनाई जा रही है वैकल्पिक व्यवस्था

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिवर्स बिडिंग शुरू की गई है। इसमें पांच लाख रुपया प्रतिमाह के हिसाब से विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। पिछले वर्ष करीब 170 डॉक्टरों की भर्ती की गई थी। इन्हें फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) में चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा गया है। वॉक-इन-इंटरव्यू के तहत जनवरी 2026 में संविदा पर 710 डॉक्टरों की भर्ती के लिए साक्षात्कार हुए हैं। विभाग में सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया था।

बन रहा है भर्ती बोर्ड

डॉक्टरों की कमी और आयोग से भर्ती में लगने वाले लंबे वक्त को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड लेवल 2 यानी एमडी-एमएस डिग्रीधारी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करेगा। साथ ही लेवल वन यानी एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सकों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूरी करेगा।

डॉक्टरों की कमी के मुख्य कारण

हर साल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 200-250 विशेषज्ञ चिकित्सक भेजे जाते हैं। इसमें करीब 25 फीसदी कार्यभार ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही गायब हो जाते हैं। लंबे समय तक गायब होने के बाद इन्हें नोटिस दी जाती है, लेकिन जब नहीं लौटते हैं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई करके उस पद को रिक्त घोषित किया जाता है। ग्रामीण इलाके से नौकरी छोड़ने वाले विशेषज्ञों ने बताया कि उन्हें आवास, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा जैसी आधारभूत सुविधा नहीं मिलती है। तमाम अस्पतालों में उपचार में प्रयोग होने वाले संसाधन भी नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में सरकारी सेवा छोड़ना विवशता होती है। निजी अस्पतालों में शहरी सुविधा के साथ ही आकर्षक वेतन भी मिलता है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

प्रदेश में कई स्तर पर डॉक्टरों की भर्ती चल रही है। नया बोर्ड भी बन रहा है। नए मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर भी कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि साल दो साल में सभी पद भर जाएंगे। हमारी कोशिश है कि मरीजों को बेहतर इलाज मिले।-अमित कुमार घोष, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

भीषण गर्मी के बीच कटौती से उपभोक्ता हुए उग्र, आधी रात को उपकेंद्रों का घेराव; कर्मियों ने खुद को किया बंद

(जीएनएस)।

लखनऊ , यूपी की राजधानी लखनऊ में बिजली संकट बना हुआ है। चार हजार उपभोक्ताओं की बिजली सोमवार रात 11:30 से मंगलवार की सुबह 4:30 बजे तक बाधित रही।

दुबग्गा क्षेत्र के एफसीआई उपकेंद्र तहत आदर्श विहार फीडर से जुड़े लगभग चार हजार उपभोक्ताओं की बिजली सोमवार रात 11:30 से मंगलवार की सुबह 4:30 बजे तक बाधित रही। उमस भरी गर्मी में घंटों बिजली गुल रहने से नाराज उपभोक्ता आधी रात में उपकेंद्र पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ती देख उपकेंद्र के कर्मचारियों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने उपभोक्ताओं को समझाकर शांत कराया और जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग लौट गए। कर्मचारियों ने बताया कि बिजली चोरी के चलते ओवरलोडिंग के कारण कई इलाकों में केबल जलने से आपूर्ति बार-बार बाधित होती है जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।

15 कर्मचारियों पर 26 हजार उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी

एफसीआई उपकेंद्र पर मौजूदा समय में 15 कर्मचारी हैं। दिन और रात की पाली में सात-सात कर्मचारी कार्य करते हैं। इन पर 26 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी है। कर्मचारियों के अनुसार यहां 30 कर्मियों की जरूरत है। उच्च अधिकारियों की उदासीनता से उपकेंद्र पर आए दिन हंगामे की स्थिति बनती है लेकिन समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

एक के बाद एक जले दो ट्रांसफार्मर

दुबग्गा क्षेत्र के प्रतीक विहार कॉलोनी में 250 केवीए ट्रांसफार्मर में आग लगने से करीब एक घंटे तक आग की लपटें उठती रहीं। इससे अफरातफरी का माहौल बना रहा। लपटों में 10 मीटर केबल भी जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। विभाग ने 400 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया लेकिन ओवरलोडिंग के कारण वह भी कुछ घंटों बाद फुंक गया। इससे करीब 10 घंटे तक लोगों को गर्मी-उमस में बिजली संकट से जूझना पड़ा सोमवार को तीसरा ट्रांसफार्मर लगाया गया जिसके बाद शाम को बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी।

15 दिन से लो वोल्टेज की समस्या

दुबग्गा पारा क्षेत्र के मुनेश्वरपुरम कॉलोनी में पिछले 15 दिन से हाई और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। क्षेत्र में एबीसी और न्यूट्रल जलने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जिम्मेदार इसका स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

केबल जलने से कई इलाकों की बिजली गुल

जीपीआरए उपकेंद्र के अंतर्गत जानकीपुरम चार नंबर चौराहे के पास पोल पर लगे केबल में आग जलने से 400 केवीए ट्रांसफार्मर से जुड़े उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसी प्रकार सोमवार रात करीब 11:30 बजे फैजुल्लागंज की श्याम विहार कॉलोनी में प्रजापति टावर के पास और मंगलवार शाम करीब 7 बजे परागी मंदिर के सामने भी केबल में आग लगने की घटनाएं हुईं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने केबल बदलकर आपूर्ति चालू की।

15 मिनट के लिए बंद हुए 11 उपकेंद्र, मचा हड़कंप

ट्रांस गोमती क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 9:30 बजे 11 उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति अचानक ठप हो गई। इससे सीतापुर रोड के बिठौली से लेकर खड़ा तक और जानकीपुरम से लेकर निराला नगर तक 15 मिनट अंधेरा छाया रहा। घटना से इलाके के बिजली अभियंताओं में हड़कंप मच गया। ट्रांसमिशन इकाई के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आंधी और बिजली कड़कने के कारण ट्रांसमिशन उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति अपने आप बंद हो गई जो 15 मिनट के बाद 9:45 बजे चालू हुई। इस दौरान अहिबरनपुर, न्यू कैंपस, इंजीनियरिंग कॉलेज, जानकीपुरम, विकास नगर, जीएसआई, जीपीआरए पुरनिया, निराला नगर, महानगर और कपूरथला उपकेंद्र प्रभावित रहे।

सेना में भर्ती कराने के आरोप में एक का कोर्ट मार्शल, दूसरा दोषमुक्त; रक्षा मंत्रालय ने दिए जांच के निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। पांच साल पहले कमांड अस्पताल में तैनाती के दौरान सेना में भर्ती कराने के नाम पर नौ लाख रुपये लेने के एक आरोप में पकड़े गए दो जवानों की जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस मामले में बीती 29 मई को 11 जीआरआरसी में आयोजित जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया को एक जवान को दोषी मानते हुए उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है।

जवान को पांच साल की सजा और सेना से सेवामुक्त कर दिया गया है। जबकि इसी आरोप में सह अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया है। एक ही आरोप में सह आरोपी को दोषमुक्त किये जाने की शिकायत के बाद फिर से मध्य कमान मुख्यालय को जांच कराने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पत्र भेजा है।

सेना मेडिकल कोर के हवलदार हरिओम सिंह चौहान की तैनाती अप्रैल 2018 से जून 2021 तक कमांड अस्पताल में थी। आरोप है कि सुरेश यादव उर्फ बबलू यादव से उनकी बेटी की मिलिट्री नर्सिंग सेवा में भर्ती कराने

के लिए हवलदार हरिओम सिंह चौहान के बैंक खाते में नौ लाख रुपये भेजे गए थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हवलदार हरिओम सिंह चौहान को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन की जांच की। जांच में सुरेश यादव की बेटी का प्रवेश पत्र मिला, जिसे एएमसी के ही हवलदार भूपेंद्र यादव ने भेजा था।

मिलिट्री इंटेलिजेंस से असम से हवलदार भूपेंद्र यादव को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। मध्य यूपी सब एरिया मुख्यालय के आदेश पर दिसंबर 2022 से 11 गोरखा राइफल्स रेजीमेंटल सेंटर में संबद्ध कर दोनों जवानों के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई।

समरी ऑफ एविडेंस में दोनों जवानों के मोबाइल फोन में प्रवेश पत्र पाए गए। हवलदार हरिओम सिंह चौहान ने ट्रायल के दौरान कहा कि उसका पत्नी से तलाक होने वाला था, तलाक में प्रतिपूर्ति के लिए ही कुछ लोगों से रुपये उधार लिया गया था, इसमें से करीब साढ़े चार लाख रुपये वापस कर दिए गए।

वहीं, सुरेश यादव उर्फ बबलू यादव की पत्नी रानी देवी ने ट्रायल के दौरान कहा कि उनके परिचित और लखनऊ में ईएमई कोर में तैनात कुलदीप यादव ने हवलदार भूपेंद्र यादव से मुलाकात करायी थी। भूपेंद्र यादव ने कहा था कि हवलदार हरिओम सिंह चौहान बेटी को मिलिट्री नर्सिंग में भर्ती कराने में मदद करेंगे।

इसके लिए 10 लाख रुपये मांगे गए लेकिन डील नौ लाख रुपये में तय हुई। बेटी ने भर्ती का फार्म भरा। प्रवेश पत्र आया तो भूपेंद्र यादव को भेजा गया। भूपेंद्र ने ही हवलदार हरिओम सिंह चौहान के मोबाइल फोन पर प्रवेश पत्र भेजा था।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने होम्योपैथी पर जिम्मेदार विमर्श की सलाह दी, सत्यापित सूचना पर भरोसा करने का किया आह्वान

एनसीएच ने सभी हितधारकों से आग्रह किया है कि वे होम्योपैथी और पंजीकृत चिकित्सकों के खिलाफ मानहानिकारक, भ्रामक और निराधार बयान देने से बचें

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) ने एक सलाह जारी कर सभी हितधारकों, मीडिया संस्थानों और आम जनता से आग्रह किया है कि वे होम्योपैथी और पंजीकृत होम्योपैथ के बारे में सोच-समझकर बयान जारी करें।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष डॉ. तारकेश्वर जैन ने सूचित किया कि आयोग होम्योपैथी में शिक्षा, अभ्यास, पेशेवर आचरण और नैतिकता के मानकों को विनियमित करने और बनाए रखने के अपने दायित्व का प्रयोग करते हुए होम्योपैथी और इसके चिकित्सकों को लक्षित करने वाले गैर-जिम्मेदाराना और निराधार बयानों के खिलाफ दिनांक 08.06.2026 को एफ. नंबर 27/2026-एनसीएच के माध्यम से एक परिपत्र जारी किया है।

आयोग ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रसारित हो रहे अपमानजनक, मानहानिकारक, भ्रामक और निराधार बयानों के मामलों का संज्ञान लेते हुए विमर्श में तथ्यात्मक सटीकता और जिम्मेदार संचार की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. जैन ने बताया कि होम्योपैथी राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है और होम्योपैथिक दवाओं का विनियमन औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत होता है। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक ढांचे के तहत संचालित किए जाते हैं और इसमें दाखिला राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) उत्तीर्ण उम्मीदवारों के माध्यम से होता है।

उन्होंने कहा कि पंजीकृत होम्योपैथ निर्धारित शिक्षा और प्रशिक्षण मानकों से गुजरते हैं और लागू वैधानिक तथा नियामक प्रावधानों के अनुसार होम्योपैथी का अभ्यास करने के लिए अधिकृत हैं।

आयोग ने संस्थानों, पेशेवर निकायों, स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे होम्योपैथी या इसके चिकित्सकों के संबंध में सार्वजनिक बयान देने से पहले उचित सावधानी बरतें और तथ्यों की सटीकता सुनिश्चित करें।

विमर्श में कहा गया है कि किसी व्यक्तिगत चिकित्सक के आचरण के संबंध में किसी भी आरोप, शिकायत या चिंता का समाधान पेशे के खिलाफ सामान्यीकृत दावों की बजाय स्थापित वैधानिक, नियामक, अनुशासनात्मक या न्यायिक तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।

डॉ. जैन ने होम्योपैथी और पंजीकृत चिकित्सकों की गरिमा, अखंडता और कानूनी स्थिति की रक्षा के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि निराधार, भ्रामक या मानहानिकारक बयान फैलाने के कृत्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है, इसमें जहां आवश्यक हो वहां कानूनी कार्रवाई भी शामिल है।

गोरखपुर में बैठक के बाद भी नहीं ढके गए नाले, खुली नगर निगम की पोल

सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निदेर्शों के बावजूद नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और जल निगम इस नाले की जिम्मेदारी लेने से मुकर रहे हैं.

(जीएनएस)।

गोरखपुरः करीब 2 साल पहले बारिश के दौरान लखनऊ में खुले नाले में गिरकर हुई एक बच्चे की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निगम क्षेत्रों में खुले नालों को ढकने का सख्त निर्देश दिया था. बावजूद इसके गोरखपुर में लापरवाही लगातार जारी है और इस तरह की दर्दनाक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं.

गोरखपुर में भी ऐसी कई घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं जिनमें सीधे तौर पर नगर निगम और ठेकेदारों की लापरवाही सामने आती है. लेकिन किसी भी प्रकार का कड़ा एक्शन ना होने से ऐसा प्रतीत होता है कि सीएम के निदेर्शों का जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है.

मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भी नहीं सुधरे हालातः अभी 2 जून को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे और उन्होंने इस गंभीर विषय को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे. लेकिन अनुपालन की बात तो दूर, लापरवाही इस कदर हावी थी कि मंगलवार 9 जून की देर शाम एक और व्यक्ति ने खुले नाले में गिरकर दम तोड़ दिया. इससे पूर्व भी पादरी बाजार से पिपराइच रोड पर निमार्णाधीन खुले नाले में गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी. शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्ती नगर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसमें एक मासूम बच्चे ने अपनी जान गवाई थी.

डीएम आवास के पास भी खुले मिले मौत के नालेः राप्ती नगर की उस घटना में खुले नाले में गिरने से निर्माण कार्य की सरिया मासूम के पेट में घुस गई थी. ईटीवी भारत ने इस घटना के बाद जब शहर के खुले नालों की जमीनी पड़ताल शुरू की तो सबसे चौकाने वाला नजारा सामने आया. ढक्कन के खुले नालों की सच्चाई दिखाई गई तो वह सहम गए. इसके

पड़ताल में पता चला कि खुद जिलाधिकारी (डीएम) आवास और कार्यालय को जाने वाली वीआईपी सड़क के किनारे के नाले भी बिना ढक्कन के खुले पड़े मिले. यहां पास के कोचिंग संस्थान के बच्चे अपनी गाड़ियां भी खड़ी करते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है.

सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर हो रही सफाईः ऐसी ही जानलेवा स्थिति शहर में कई अन्य जगहों पर भी साफ तौर पर दिखाई दी. यही नहीं, नगर निगम की लापरवाही इस दौरान यह भी देखने को मिली कि गहरे 15 फीट के नाले में बिना किसी सुरक्षा मानक, मास्क और ग्लब्स के बगैर ही सफाई कर्मचारियों से काम लिया जा रहा था. इस अव्यवस्था पर बेतियाहाता क्षेत्र के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है. इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे कूड़े को नालों में न फेंकें.

अपर नगर आयुक्त ने दिया कार्रवाई का आश्वासनः जब ईटीवी भारत इस गंभीर समस्या को अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार के संज्ञान में लाया तो वह पहले तो चलाए जा रहे सफाई अभियान की बातें करने लगे. लेकिन जब उन्हें जिलाधिकारी आवास और कार्यालय की तरफ बिना ढक्कन के खुले नालों की सच्चाई दिखाई गई तो वह सहम गए. इसके बाद उन्होंने बात संभालते हुए कहा कि इसको दिखवाएंगे और दो दिन के भीतर यहां मजबूत ढक्कन लगवा दिया जाएगा. अब मंगलवार 9 जून को हुई ताजा घटना के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है.

जिम्मेदारी लेने से मुकर रहे शहर के विभागः जिस नाले में गिरकर 40 वर्षीय शख्स की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेने को शहर का कोई भी प्रमुख विभाग तैयार नहीं है. ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर लावारिस छोड़ दिया गया यह नाला है किसका. फातिमा अस्पताल के पास बने इस नाले के निर्माण से नगर निगम ने साफ तौर पर अपना हाथ खींच लिया है. नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार का कहना है कि यह नाला नगर निगम के अधिकार क्षेत्र का नहीं है.

PWD और जल निगम ने भी पल्ला झाड़ाः दूसरी तरफ जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार का स्पष्ट कहना है कि यह नाला उनके विभाग का नहीं है. तो लोक निर्माण विभाग (PWD) खंड तीन के अधिशासी अभियंता उदय प्रकाश भी कहते हैं कि यह नाला पीडब्ल्यूडी का नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गोरखपुर शहर में कोई बाहर से आकर गुपचुप तरीके से नाला बनाता है और चला जाता है. और किसी भी जिम्मेदार सरकारी विभाग को इसकी भनक तक नहीं होती.

अज्ञात मृतक की पहचान में जुटी शाहपुर पुलिसः फिलहाल इस ताजा हादसे में जिस व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और शाहपुर थाना पुलिस पहचान में जुटी है. वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि नाले पर तुरंत स्लैब पड़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाया है. हैरानी की बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता धीरज गुप्ता कहते हैं कि शाहपुर क्षेत्र में खुले नाले में गिरने से हुई इस घटना के बाद भी शहर और जिला प्रशासन में कोई हलचल तक नहीं हुई. इसके लिए दोषी कौन है और सजा किसे मिलेगी, यह सवाल आज भी अनुत्तरित खड़ा है.

सरिया धंसने से पहले भी हो चुकी हैं कई मौतेंः खुले नाले में गिरकर किसी आम नागरिक के मर जाने की यह शहर में कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले 12 मई को देवरिया जिले के निवासी मजदूर हंसराज की पादरी बाजार में नाले में गिरकर मौत हो गई थी. वह नाला भी निमार्णाधीन था और उसे ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे हंसराज के शरीर में सरिया धंस गई थी. इसी तरह चिलुआताल क्षेत्र के मानबेला में 18 फरवरी को कन्हैया नाम का एक बालक साइकिल सहित खुले नाले में गिर गया था और सरिया धंस जाने से उसकी भी मौत हो गई थी.

अधिकारियों के कागजी दावों की खुली पोलः बीते 15 मई को भी बरगदवा में पैदल जा रहा एक व्यक्ति अचानक खुले नाले में गिर गया था, लेकिन आसपास के लोगों ने देख लिया और उसे सकुशल बाहर निकाल दिया. ये घटनाएं तो महज एक बानगी हैं, क्योंकि शहर में अन्य कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिनमें लोग खुले नाले में गिरकर जान गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं. शायद ऐसी ही घटनाओं को लेकर 2 जून की उच्च स्तरीय बैठक में जिम्मेदारों ने गहरी चिंता जताई थी. उस बैठक में मंथन के बाद फैसला लिया गया था कि खुले नालों पर शीघ्र स्लैब डलवा दिए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए.

सिर्फ वादों में उलझकर रह गए सीएम के निदेर्शः शासन ने भी इसे बेहद गंभीरता से लिया था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे रखा है कि नाले ढके जाने में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. लेकिन लेटलटीफी और घोर लापरवाही की वजह से मंगलवार को भी एक ऐसी ही दर्दनाक घटना दोबारा घट गई. पादरी बाजार क्षेत्र में फातिमा बाईपास के पास खुले नाले में एक अज्ञात युवक गिर गया, जिसकी सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक को नाले से बाहर निकलवाकर एम्बुलेंस के जरिए तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

लापरवाही के कारण उजड़ रहे हंसते-खेलते परिवारः अगर सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों ने समय रहते अमल किया होता, तो मंगलवार को पादरी बाजार में एक और बेकसूर युवक की जान नहीं जाती. सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि वह युवक कौन था और कहां का निवासी था, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है. युवक के अपने परिजन घर पर उसके सकुशल लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे. लेकिन अव्यवस्थाओं को सही करने के जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसी मौतों पर कोई दर्द नहीं होता है और ये मामले सिर्फ दावों और दिशा-निर्देशों में ही उलझ कर रह जाते हैं. यदि समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई तो बारिश का सीजन करीब होने के कारण ऐसी घटनाएं अभी और बढ़ सकती हैं.

लखनऊ में बिजली भाग ने सुबह 4 बजे मारा छापा, चोरी से चार्ज हो रहे थे 35 ई-रिक्शा; कटिया से चलते मिले एसी

(जीएनएस)।

लखनऊ। पुराने लखनऊ में बिजली चोरी करने से चोर बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ मध्य जोन में लगातार लाइन लॉस कम करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सुबह चार बजे छापा मारा गया।

पुराने लखनऊ के यासीनगंज जो चोरी बहुल क्षेत्र हैं, यहां प्रवेश करते ही दो गोदामों में टीमों ने जांच की तो चोरी मिली। यहां टीम ने पाया कि दो ई रिक्शा गोदाम संचालकों द्वारा चोरी की बिजली से 35 ई रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे। बता दे कि एक ई रिक्शा चार्ज करने में प्रतिदिन नौ से दस यूनिट बिजली की खपत होती है।

गोदाम का कनेक्शन काट दिया गया है और मीटर उखाड़ लिए गए हैं।

अभियंताओं ने संबंधित चोर के खिलाफ बिजली चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कराया है और आठ से दस लाख रुपये जुमार्ना भी लगने की संभावना है। क्योंकि बिजली चोरी दस किलोवाट से अधिक दोनों परिसर में पकड़ी गई है।

मुख्य अभियंता रवि के मुताबिक टीम ने यासीनगंज में आगे भी अभियान चलाया तो 12 घरों में कटिया व मीटर बाइपास करके चोरी करते हुए लोग पाए गए। उन्होंने बताया कि अभी तक टीम सुबह चार से पांच बजे के बीच छापा मारती थी तो बिजली चोर सचेत हो जाते थे। इस बार रणनीति बदलते हुए एक घंटे पहले यानी तड़के तीन बजे से सुबह चार बजे के बीच छापा मारा गया। इनमें कुछ चोरों ने विजिलेंस टीम को बताया कि सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगाकर सोते हैं, जिससे कटिया व बाइपास को सुबह जल्द उठकर सामान्य किया जा सके, लेकिन टीम ने उससे पहले ही छापा मार दिया। बिजली विभाग को लगातार यासीनगंज से हर माह लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था।

रसोइयों के कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने की दिशा में पंजीकरण शुरू, बीएसए को दिए गए निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए रसोइयों के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) का कार्य प्रारंभ हो गया है। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को जल्द से जल्द पात्र रसोइयों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। अपर राज्य परियोजना निदेशक प्रेम रंजन सिंह ने जारी निर्देशों में कहा है कि बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की वार्डेन तथा रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्रदान किया जाना है। इसके लिए सभी लाभार्थियों का पंजीकरण आवश्यक है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार रसोइयों के पंजीकरण के दौरान कुछ तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं सामने आ रही हैं। विशेष रूप से रसोइयों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही हैं। इस संबंध में उच्च स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पंजीकरण कार्य सुचारु रूप से पूरा कराया जा सके। शिक्षा विभाग का कहना है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से हजारों रसोइयों और अन्य कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा इलाज के दौरान आर्थिक बोझ भी कम होगा। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से पंजीकरण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा: कश्मीर से लौट रही स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई, लखनऊ के 11 यात्री घायल

(जीएनएस)।

अमरोहा। गंगा एक्सप्रेस वे पर सैदनगली थाना क्षेत्र में चालक को झपकी आने के बाद अनियंत्रित हुई कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में लखनऊ के नखासा चौक निवासी एक ही परिवार के 11 लोग घायल हो गए। इस हादसे में बच्चे भी घायल हुए हैं।

नखासा चौक निवासी अबुबकर व व मोहम्मद उमर परिवार के लोगों के साथ कार में सवार होकर जम्मू-कश्मीर घूमने गए थे। कार में बच्चे भी सवार थे। बुधवार सुबह सभी लोग वापस लौट रहे थे।

चालक को झपकी आने से टकराई कार

मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे पर हसनपुर तहसील के सैदनगली थाना

क्षेत्र में खरसौली गांव के नजदीक चालक को झपकी आने से उनकी स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकरा गई। सभी लोग क्षतिग्रस्त कार में फंस गए। राहगीरों ने कार में फंसे यात्रियों को बमुश्किल बाहर निकाला।

हादसे में आमना पुत्री आमिर (16), अबूबकर पुत्र अयाज (40), कुलसुम पत्नी अबूबकर (38), सिबरा पुत्री आमिर (10), अफ्फान पुत्र अबूबकर (8), अफीफा पुत्री अबुबकर (6), उमर पुत्र ऐजाज अहमद (30), हिना पत्नी उमर (28), जुनैरा पुत्री आरिफ (15), मोहम्मद पुत्र उमर (10) तथा हादिया पुत्री उमर (14) घायल हो गए। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे पर सैदनगली थाना क्षेत्र में कार डिवाइडर से टकराने से हादसा हुआ है। जिसमें लखनऊ के यात्री घायल हैं।

लखनऊ के माल में पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या:घर के फर्श पर पड़ी मिली लाश, आरोपी पति ने भी खाया जहर; अस्पताल में भर्ती

(जीएनएस)।

मलिहाबाद, लखनऊ में माल इलाके में सोमवार दोपहर पति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। घर के फर्श पर महिला का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। घटना के बाद आरोपी पति ने जहर खा लिया। जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक आजाद नगर निवासी जितेंद्र प्रताप सिंह (55) ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी मोनिका सिंह (47) पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में मोनिका की मौके पर ही मौत हो गई। उनका शव घर के एक कमरे में पड़ा मिला।

पति को पुलिस ने हिरासत में लिया

घटना के बाद आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसकी हालत बिगड़ने पर चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। डॉक्टरों ने आशंका जताई कि उसने किसी विषाक्त (जहरीला) पदार्थ खा लिया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

मोनिका के बड़े बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

मृतका के बड़े बेटे अंशुमान सिंह की तहरीर पर माल थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया

गया है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है।

डीसीपी नॉर्थ ट्विंकल जैन ने बताया सोमवार दोपहर माल थाने पर सूचना मिली कि जितेंद्र नाम के युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम से भेज दिया है। बेटे से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

आरोपी के पिता दीवान के पद पर थे तैनात

आरोपी जितेन्द्र प्रताप सिंह के पिता चन्द्रभान सिंह माल थाने में दीवान के पद पर तैनात रहे हैं और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मृतका के परिवार में दो बेटे और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है।

बहन का आरोप घर वालों को पैसे का घमंड

मृतका की बहन और भाई ने रोते हुए कहा कि बहन के घर वालों को पैसे का बहुत घमंड है। जिसके चलते उन्होंने उसकी बहन की हत्या कर दी। और उसके पीछे जितने भी लोग शामिल है कोई बचना नहीं चाहिए।

ससुर ने कहा नहीं मिली जानकारी

ससुर सीबी सिंह ने बताया कि बेटे के साथ दोपहर बारह बजे भोजन किया था। एक बजे तक आराम करने के बाद पैदल काम से बाजार की तरफ चले गए। पोते को फोन किया तो उसने कहा कि आधे घंटे बाद घर आएंगे। इसके बाद वह घर आकर अपने कमरे में लेट गए।

जब पौत्र घर पहुंचा और उसने कमरा खोला तो जानकारी हुई। हालांकि, ससुर की यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है। उधर, घटना के बाद परिवारजन ने नारायणपुर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया।

देवीपाटन में हिंदू सम्मेलन के साथ कार्यक्रम संपन्न:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव पर आयोजित सात दिवसीय कार्यक्रम का समापन

(जीएनएस)।

तुलसीपुर, बलरामपुर, विश्व हिंदू महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित सात दिवसीय कार्यक्रम का समापन मंगलवार को देवीपाटन मंदिर परिसर में हिंदू सम्मेलन के साथ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकताओं ने भाग लिया।

देवीपाटन मंदिर स्थित गोरख मंडपम सभागार में आयोजित इस हिंदू सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चौधरी विजय सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवा ध्वज फहराकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम में विश्व हिंदू महासंघ अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र पाठक मुख्य अतिथि रहे। संयोजक मनोज प्रजापति, किन्नर प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा नंद गिरी और मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गंगा शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में

उपस्थित थे।

वक्ताओं ने अपने संबोधन में सनातन धर्म की मजबूती के लिए हिंदू समाज को एकजुट होने का आ'ान किया। उन्होंने जोर दिया कि जब तक हिंदू समाज जातियों में बंटा रहेगा, तब तक सनातन धर्म सशक्त नहीं हो सकेगा। समाज की एकता से ही सनातन धर्म और राष्ट्र दोनों मजबूत होंगे।

जिला कार्यसमिति सदस्य जीवन लाल कसौधन और मिथिलेश गिरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने सामाजिक समरसता और संगठन की मजबूती पर बल देते हुए उपस्थित लोगों को एकजुटता का संकल्प दिलाया।

इस अवसर पर विजय प्रताप सोनी, जय सिंह, मातेश्वरी त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू महासंघ ने 5 जून से सात दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस दौरान गांवों में दीप प्रज्वलन, कीर्तन, रक्तदान शिविर सहित विभिन्न सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां आयोजित की गईं। इस सात दिवसीय श्रृंखला का समापन हिंदू सम्मेलन के साथ हुआ।

लखनऊ में उद्यान अधिकारी को ठेकेदार ने दी धमकी:कमरे में घुसकर कहा जान से मार दूंगा; जुमार्ना लगाने से था नाराज

(जीएनएस)।

लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उद्यान अधिकारी को एक ठेकेदार ने कमरे में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इस दौरान ठेकेदार ने आपत्तिजनक शब्द भी कहे। इस मामले को लेकर अधिकारी ने प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार से लिखित शिकायत की है।

ठेकेदार पर धमकी और अभद्रता का आरोप

एलडीए के उद्यान अधिकारी ने उपाध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर बताया है कि गोमती रिवर फ्रंट और अन्य पार्कों में कराए जा रहे उद्यानिक कार्यों के निरीक्षण के दौरान कई बार सिंचाई व्यवस्था में कमी, कूड़ा-करकट का जमाव और पौधों की

कटाई-छंटाई में लापरवाही पाई गई। 14 दिसंबर 2025 को उद्यान निरीक्षक आशीष ने अपनी रिपोर्ट में इन कमियों का उल्लेख किया था।

आरोप है कि कमियां दूर करने के लिए कहने पर ठेकेदार ने फोन पर अधिकारियों से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और नौकरी खत्म कराने की धमकी दी।

इसके बाद 22 जनवरी 2026 को उद्यान निरीक्षक शालिनी ने गोमती बैराज से हनुमान सेतु तक निरीक्षण के दौरान कार्यों में खामियां मिलने की रिपोर्ट दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है।

ठेकेदार पहले भी कर चुका है अभद्रता

उद्यान अधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि ठेकेदार पूर्व में भी कई बार अभद्रता कर चुका है। आरोप है कि उसके द्वारा एक व्यक्ति के माध्यम से जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों और पुलिस को भी दी गई थी।

लखनऊ में पक्का पुल से सीतापुर रोड तक 15 मीटर चौड़ी होगी बंधा रोड, 10 लाख की आबादी को मिलेगा फायदा

अलीगंज स्टेडियम में स्वीमिंग पूल और बैडमिंटन कोर्ट, जानकीपुरम में कम्यूनिटी सेंटर का भी निर्माण कराया जाएगा.

(जीएनएस)।

लखनऊ : पक्का पुल से सीतापुर रोड तक 3.37 किलोमीटर लंबी बंधा रोड 15 मीटर तक चौड़ी होगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 38 करोड़ रुपये की लागत से स्थल पर कार्य शुरू करा दिया है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को परियोजना का निरीक्षण करके इस वर्ष के अंत तक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं.

उन्होंने बताया कि पक्का पुल से प्रियदर्शिनी योजना होते हुए सीतापुर रोड से कनेक्ट होने वाली यह बंधा रोड वर्तमान में 5 मीटर चौड़ी है. इस रोड पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है. यहां आये दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जोकि पीक आवर्स में बढ़ जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए बंधा रोड को 15 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा. जिसके लिए मौके पर मिट्टी भरायी का कार्य शुरू करा दिया गया. दिसम्बर, 2026 तक कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा.

बंधा रोड को 15 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा.

बंधा रोड का चौड़ीकरण होने से खदरा, मदेयगंज, फैजुल्लागंज, प्रियदर्शिनी योजना समेत आसपास की लगभग 10 लाख की आबादी को बड़ी राहत मिलेगी. निरीक्षण में मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा, जोनल अधिकारी माधवेश कुमार एवं वंदना पाण्डेय, नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह, अधिशासी अभियंता अजीत

कुमार एवं नीरज कुमार समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.

अलीगंज स्टेडियम में लोगों को मिलेगी सुविधा.

अलीगंज स्टेडियम में बनेगा स्वीमिंग पूल : अलीगंज स्थित एलडीए स्टेडियम में स्वीमिंग पूल, इनडोर बैडमिंटन कोर्ट व नया बास्केटबॉल कोर्ट बनेगा. इससे लोगों को नयी और बेहतर खेल सुविधाएं प्राप्त होंगी. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्टेडियम का निरीक्षण करके इस सम्बंध में निर्देश दिये हैं. स्टेडियम में पहले से निर्मित जिम अभी निष्प्रयोज्य है. उपाध्यक्ष ने जिम में सुविधाओं को उच्चीकृत करके इसे शीघ्र संचालित करने के भी निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्यों को समय से पूरा न करने पर कार्रवाई की जाएगी.

जानकीपुरम में कम्यूनिटी सेंटर व हॉर्टीकल्चर के कार्य कराये जाएंगे.

जानकीपुरम में कम्यूनिटी सेंटर बनेगा : जानकीपुरम में कुर्सी रोड पर सरगम अपार्टमेंट के पास रिक्त पड़ी लगभग 14,800 वर्गमीटर भूमि पर कम्यूनिटी सेंटर का निर्माण व हॉर्टीकल्चर के कार्य कराये जाएंगे. उपाध्यक्ष ने स्थल निरीक्षण करके इस बाबत निर्देश दिये हैं. उपाध्यक्ष ने जानकीपुरम में मौर्या विहार से जानकी विहार कालोनी के मध्य 1600 मीटर लंबे आरसीसी नाले के निर्माण कार्य की प्रगति भी देखी. 3 करोड़ रुपये की लागत से नाले का निर्माण होने से 2 लाख की आबादी को जलभराव की समस्या से निजात मिलेगा.

आगरा में बनेगा अटल मेमोरियल, लखनऊ एक्सप्रेसवे से दिखेगी 65 फीट ऊंची प्रतिमा, ओपन एयर थिएटर व कैफे जैसी सुविधाएं

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास फतेहाबाद के लुहारी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 65 फीट ऊंचा अटल मेमोरियल बनाएगी।

(जीएनएस)।

आगरा। उप्र सरकार लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास नया पर्यटन आकर्षण विकसित करेगी। फतेहाबाद के लुहारी में लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना के मध्य पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को अटल मेमोरियल में संजोया जाएगा। यहां वाजपेयी की 65 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी।

लखनऊ एक्सप्रेसवे से गुजरते समय दूर से ही यह प्रतिमा नजर आएगी। यहां ओपन एयर थिएटर, कैफे बनाने के साथ ही पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

प्रतिमा के पीछे सघन हरियाली विकसित की जाएगी। अटल मेमोरियल को पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित

किया जाएगा। लखनऊ में प्रेरणा स्थल में लगाई गईं प्रतिमाएं भी 65 फीट ऊंची हैं।

यमुना किनारे बने प्राचीन शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर, अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक स्थल है। यहां केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से सुंदरीकरण और विकास के काम कराए जा रहे हैं। प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार, घाटों के निर्माण, मंदिर कारिडोर, प्राचीन कुंड का जीर्णोद्धार आदि काम कराए जा चुके हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री की 65 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी,

पूर्व प्रधानमंत्री के पैतृक स्थल पर अभी काम किया जाना है। सरकार की बटेश्वर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और उसे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, शिकोहाबाद के ईको टूरिज्म केंद्र रापड़ी और जैन तीर्थ स्थल से जोड़कर पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल बनाने की योजना है। इसमें अटल मेमोरियल भी जुड़ेगा। प्रदेश सरकार ने 22.5 करोड़ रुपये उप्र पर्यटन विभाग को अटल मेमोरियल के लिए स्वीकृत किए हैं। प्रतिमा बनवाने का काम संस्कृति विभाग करेगा।

बटेश्वर से करीब 40 किमी दूर

आगरा से लुहारी लखनऊ एक्सप्रेसवे के 37वें किमी पर है। यहां से बटेश्वर करीब 40 किमी की दूरी पर है। इससे पर्यटकों को 60 किमी के क्षेत्र में कई पर्यटन आकर्षण मिलेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास भी होगा।

बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ पर युवक ने की अभद्र टिप्पणी, बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की

(जीएनएस)।

बलरामपुरः जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता दिख रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो नहर बालागंज पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है. 41 सेकंड के इस वायरल वीडियो

में एक युवक की पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के दौरान सेल्समैन से किसी बात पर कहा सुनी होती है. जिसके बाद युवक मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र टिप्पणी और गाली देते हुए देखा जा रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गालीबाज युवक की गिरफ्तारी की मांग की है. बलरामपुर सदर से बीजेपी विधायक पलटू राम ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।